



VISION IAS

www.visionias.in



GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1025)

Name of Candidate	Zamir Zamir		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	42370
Center	Mukherjee Nagar	Date	18/09/17

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

- Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
- There are TWENTY questions printed in ENGLISH & HINDI इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
- All questions are compulsory.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
- Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

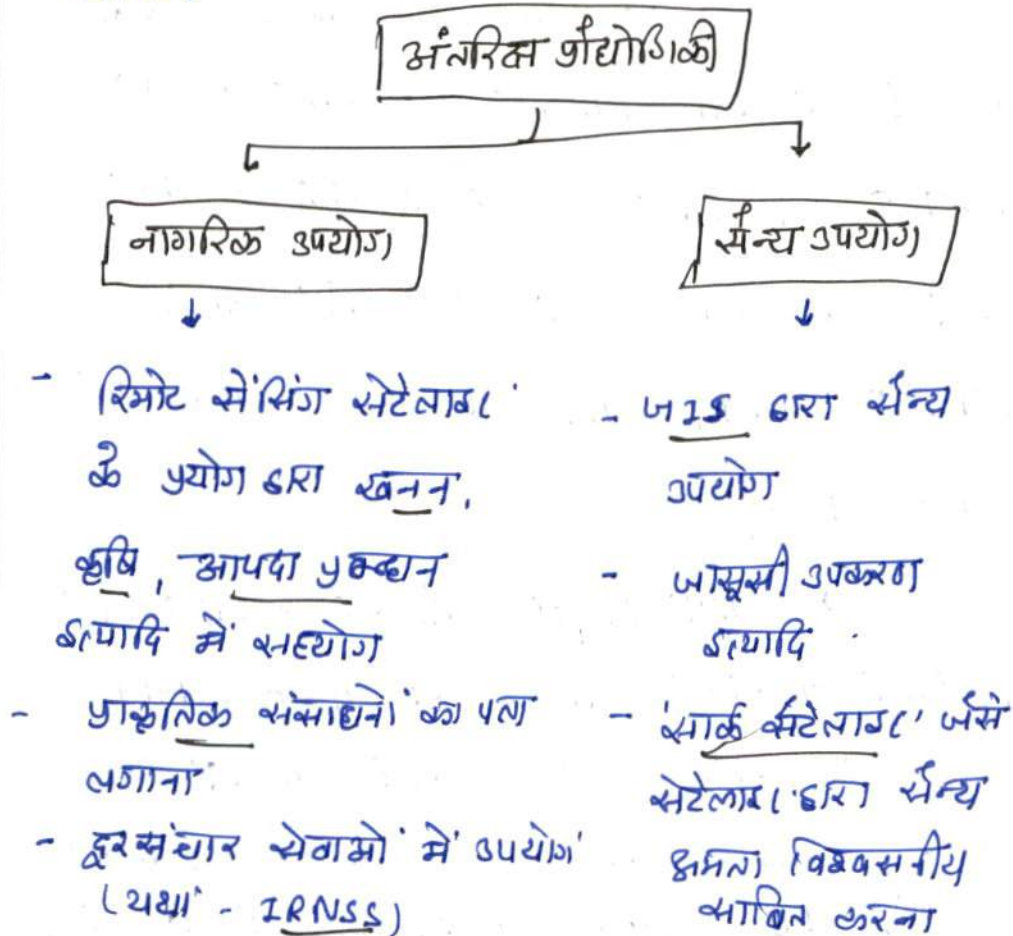
Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

12.5X20=250

1. The dual use nature of space technology enables its utilisation for civilian as well as military purposes. In this context, examine the need for a Space Security Policy in India.

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग की प्रकृति नागरिक एवं साथ ही सैन्य प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग को सक्षम बनाती है। इस संदर्भ में, भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा नीति की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किसी भी राष्ट्र की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा एवं मानवीय सेवाओं की दोहरी उपलब्धता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही है।



भारत में अंतरिक्ष ज्योडिक्ली -

भारत में अगस्त 1969 में अपनी स्थापना पश्चात ही अंतरिक्ष ज्योडिक्ली के बिस्तार, विकास हेतु प्रयासरत रही है। हाल ही में 104 अक्टोबर एक साथ दोड़कर भारत ने कीर्तिमान बनाया है।

भारत में आंतरिक सुरक्षा नीति : आवश्यकता -

- भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति में अंतरिक्ष ज्योडिक्ली के उपयोग की आवश्यकता है। अगस्त 1969 में वल्लभ भट्ट के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट बना रहा है परंतु इसका अधिकांश समय, ध्यान व्यावसायिक उपयोग वाले प्रोजेक्ट पर है।

→ आप पुराने आंतरिक सुरक्षा खतरा परम्परागत न होकर हारजिज होगा है जिसमें परम्परागत तरीकों के साथ-साथ अंतरिक्ष ज्योडिक्ली, आदित्य कक्ष में पुनर्निर्माण भी शामिल है। यथा - 2008 में पुनर्निर्माण में JPS का उपयोग।

- अंतरिक्ष जॉयोरिक्की के माध्यम से अपराधियों की ट्रेकिंग, मोबाइल पर लोकेशन पता लगाना बायापि आसानी से हो सकता है।

सरकार द्वारा उठाये कदम -

हाल ही में सरकार द्वारा ~~एक~~ इसरो को सुरक्षा नीति में शामिल करने हुए अंतरिक्ष चिंज बनसे का फैसला किया गया है।

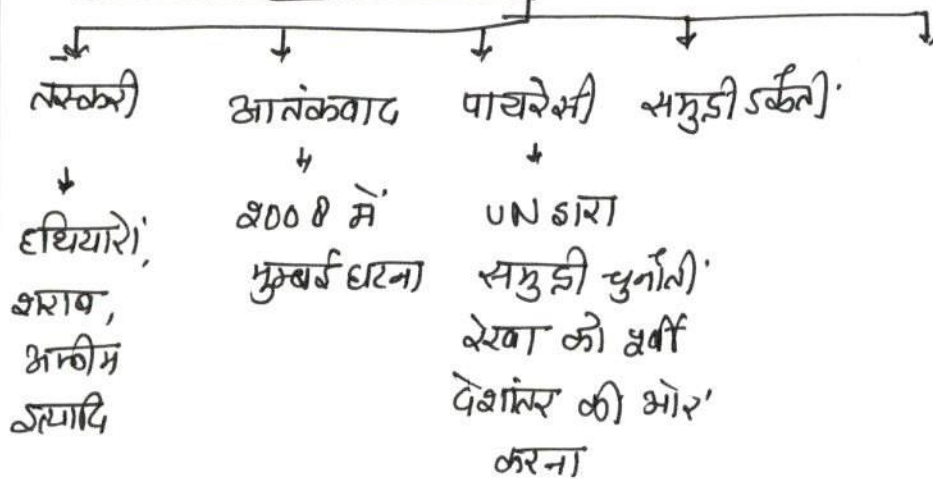
2. What are the issues associated with coastal security in India? In this context, discuss whether a Central Marine Police Force can help in addressing these issues.

भारत में तटीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे क्या हैं? इस संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि क्या एक केंद्रीय समुद्री पुलिस बल (सेंट्रल मरीन पुलिस फोर्स) इन समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकता है?

भारत एक विशाल विविधता वाला

राष्ट्र है जिसकी एक लम्बी सीमा समुद्र से
जोड़ी है, अतः तटीय सुरक्षा भारतीय आंतरिक
एवं बाहरी सुरक्षा का एक प्रमुख बिन्दु रहा है।

तटीय सुरक्षा के मुद्दे -



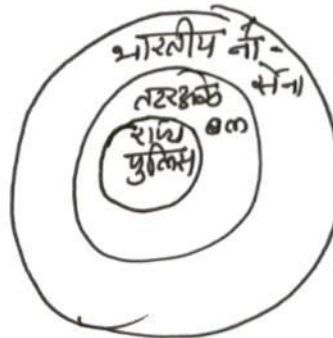
तटीय सुरक्षा के मुख्य मुद्दों में
तटीय निगरानी, पर्यवेक्षण को सुस्त, सुव्यवस्था
बनाना शामिल है।

सेंडल मेरिन पुलिस लोर्स -

हाल ही में यह सुझाव दिया गया है कि तटीय सुरक्षा हेतु माला से सेंडल मेरिन पुलिस लोर्स का गठन किया जाये।

वर्तमान में तटीय सुरक्षा पल, तटरक्षक बल, नेवी वायादि तटीय सुरक्षा का कार्य करती है जिसके अन्तर्गत विस्तरीय गांचा है -

विस्तरीय तटीय
सुरक्षा गांचा -



आवश्यकता

- तटीय सुरक्षा की विभिन्न चुनौतियों के मध्य समन्वय बढ़ेगा
 - तटीय सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम है, अतः एकीकृत एवं समन्वित नीति
 - राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से परे होगी
- आगे की राह -

वस्तुतः आवश्यकता सभी

बनों में आणसी सामंजस्य द्वारा समन्वयकारी
नीति अपनाने की है।

3. Cyber terrorism holds serious potential to paralyze economic and financial institutions in India. What are the issues and challenges w.r.t. India's cyber security? What initiatives has the Govt taken to address the same?

साइबर आतंकवाद भारत में आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं को शक्तिहीन करने संबंधी गंभीर क्षमता रखता है। भारत की साइबर सुरक्षा से संबंध मुद्दे और चुनौतियाँ क्या हैं? इनका समाधान करने के लिए भारत सरकार ने कौन-सी पहलें की हैं?

साइबर आतंकवाद से नापूर्य " साइबर,
कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से होने वाले
आक्रमण से है जिसके अन्तर्गत मैलवेयर,
वायरस द्वारा लाइव्स, ई-मेल आदि को हँक,
कमप्ट किया जाता है।"

साइबर आतंकवाद आप्त भारत की
आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा समक्ष एक बड़ा
खतरा बन कर उभरा है। हाल ही में बेसमवेत
वानाडार वायरस, इसरो की ऑलिम्पिक साइट
तक वायरस पहुंचना इसकी गंभीरता को प्शानि है।

साइबर सुरक्षा के चुइये -

साइबर सुरक्षा में ऐली
वायरस प्रणाली, बैंको एवं वित्तीय संस्थानों को
प्रभावी बनाए, जन जागरूकता, वित्तीय एवं
डिजिटल साक्षरता का प्रसार महत्वपूर्ण है।

साबर सुरक्षा की चुनौतियाँ

- हैकिंग - कम्प्यूटर की माइल्स को हँक कर देना।
- वायरस, मालवेयर - वायरस द्वारा कम्प्यूटर प्रणाली को क्षतिग्रस्त करना।
- मिशिंग - बैंक अकाउंट तक पहुँच खोजना।
- डोजन हॉर्स
- बोटनेट इत्यादि

हाल ही में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में सैदा लगाकर कई लोगों के धन में से निकालने की घटना।

सरकार द्वारा पहल -

- सरकार द्वारा "कम्प्यूटर इमरजेन्सी रेस्पॉन्स टीम (CERT-IN) का गठन किया गया है ताकि साबर आतंकवाद पर त्वरित कार्यवाही की जा सके।
- नेशनल इंटेलेजेंस कमिशन (NIC) की स्थापना
- पंचायतों तक डिजिटल साक्षरता हेतु PM - DIKHA कार्यक्रम, भारतनेट इत्यादि।

- हाल ही में विश्व बैंक द्वारा सभी 'सार्वजनिक' बैंकों को आरक्षित सुरक्षा सेल गलत का निर्देश दिया।

सुझाव

- विलियम एवं डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा दिया जाये।
- डिजिटल समीक्षण
- विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं में समन्वय का विकास किया जाये।

4. Critically examine the feasibility of fencing the Indo-Myanmar border as a strategy to contain insurgency given the existing Free Movement Regime (FMR) between the two countries.

उग्रवाद को नियंत्रित करने की रणनीति के रूप में भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने संबंधी व्यवहार्यता का, दोनों देशों के बीच मौजूदा मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime) के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

भारत उग्रवाद, आतंकवाद की समस्या से ग्रसित रहा है जिसके अन्तर्गत पड़ोसी देशों तथा - बंगलादेश, म्यांमार के मार्ग से उग्रवादी संगठन हथियार वत्यादि का कार्य करते हैं।

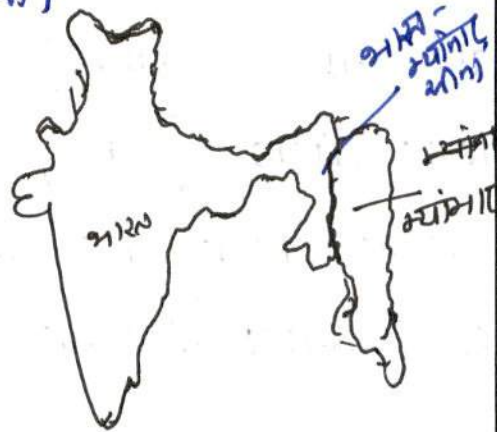
भारत - म्यांमार सीमा : बाड़ की व्यावहार्यता

म्यांमार भारत का पड़ोसी राष्ट्र होने के साथ एक लम्बे समय तक सैनिक शासन से पीड़ित भी रहा है।

आवश्यकता -

- उग्रवादी संगठनों की आवाजाही रोकने हेतु
- सीमा पार शरणार्थियों की समस्या रोकने हेतु
- पकिस्तान, सफ़र सुरक्षा प्रणाली बनाना
- पूर्वोत्तर राज्यों को विकास की दृष्टि में लाने के साथ सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता देना

- भारत म्यांमार सीमा बनने, नदियों, पहाड़ों द्वारा बाधित है, इस के माध्यम से उद्योगों के आवागमन में कमी आयेगी



आवश्यकता नहीं .

- म्यांमार द्वारा भारत की उद्योगों को रोकने द्वारा हाल में हॉट परस्यूट में मदद की
- सीमा - पार अटके सम्बन्ध
- स्थानीय आवाजाही पर रोकें लगेगी
- स्थानीय व्यापार पर गलत प्रभाव
- आपसी सम्बन्धों में दूरी आयेगी

भारत म्यांमार एक मुक्त आवागमन व्यवस्था आपस में साझा करते हैं जिससे सांस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्धों का साधा-उदात्त किया जाता है इसीलिए पूर्वोत्तर के राज्यों द्वारा बाड़ का विरोध किया जा रहा है

आगे की राह -

भारत को बिजनेस क्षेत्रों में
ज्यादा उत्तुंग धारणा से संयोजित हो रही है,
वहाँ बस के साथ अन्य लेजर तकनीकों,
'स्मॉट सेंसिंग तकनीकों', नाइट विजन कैमरा का
उपयोग किया जाना चाहिए तथा स्थानीय भाषाओं
को विश्वास में किया जाना चाहिए।

5. What do you understand by 'lone wolf attacks'? In the wake of increasing lone wolf attacks across the globe, assess India's vulnerability to such attacks. Also, suggest measures that can prevent such attacks.

'लोन वुल्फ हमलों' से आप क्या समझते हैं? विश्व भर में बढ़ते लोन वुल्फ हमलों को देखते हुए इस प्रकार के हमलों के प्रति भारत की सुभेद्यता का आकलन कीजिए। साथ ही, इस प्रकार के हमलों के रोकथाम हेतु उपाय सुझाइए।

लोन वुल्फ हमलों से नापर्य बिना किसी आतंकवादी संगठन की मदद के अकेले आतंकवादी विचारधारा से प्रभावित होकर आतंकवादी धरनाये करना है। हाल ही में लंदन, तुसेल्स, बार्सिलोना (स्पेन) आदि स्थानों पर इस प्रकार की धरनाये विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।

भारत की सुभेद्यता -

भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक राष्ट्र है जिसमें विभिन्न धर्म, पंथ के लोग निवास करते हैं।

- आतंकवादी धरनाओं के प्रति बढ़ती सामाजिक नेटवर्किंग के माध्यम से
- युवा वर्ग का इस ओर रुखाना (पथ - हाल ही में केरल में कई युवाओं को

IND से संपर्क रखते हुए पाया गया।

- मुसलमान युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के कारण आतंकवाद हो सकता है।
- जैसादी आक्रमण के नाम पर लोगों को आकर्षित करना।
- भारत के पड़ोसी राष्ट्रों यथा - अफगानिस्तान, ^{बंगलादेश आदि} पाक, में बढ़ती धार्मिक अट्टहासवाद।

भारत : सुमेधा नहीं -

- जहाँ विश्व के अन्य दुर्गतिम सभ्यताएँ इसके पक्ष में जा रहे हैं, भारतीय मुसलमान इसके विरोध में हैं।
- भारत में इस्लाम बुरफी द्वारा के माध्यम से आया है जिससे यहाँ धार्मिक उपरतावाद की भावना है।
- भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों हेतु प्राथमिक अधिकार व संरक्षण (14 - 20 - 30) तक।

संभाव -

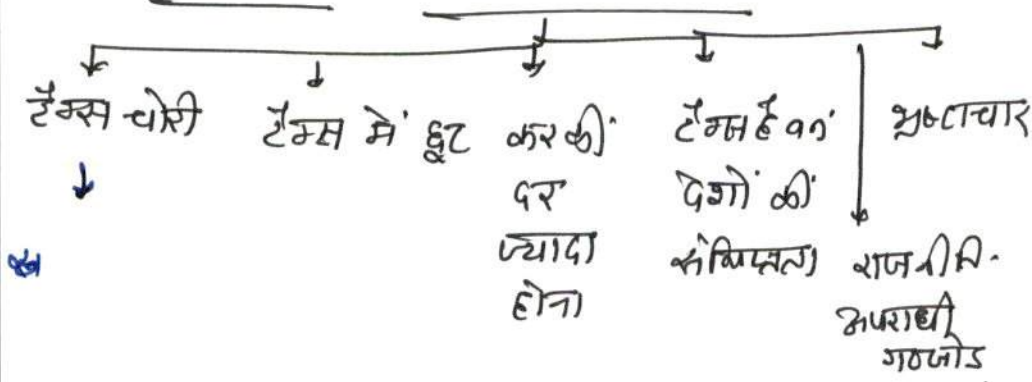
- ▲ भारत सरकार को जागरूक सिनियोरिटी को
कड़ा करना चाहिए तथा युवा वर्ग को इस
कोषे बाध्यित होने से बचाया जाना चाहिए।
- ▲ अल्पसंख्यक समुदाय हेतु सामुदायिक विकास
की योजनाएं बनाना, शैक्षिक जागरूकता
बढ़ाना शामिल।

6. What are the factors that lead to generation of black money in India? Discuss the role played by India both domestically and internationally to neutralise the menace of money laundering and black money.

भारत में काले धन के सृजन की परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले कारक क्या हैं? घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग तथा काले धन के खतरे को निष्प्रभावी करने में भारत की भूमिका की चर्चा कीजिए।

भारत में काला धन एक मुख्य
सुरक्षा चुनौती रहा है तथा समानांतर अर्थव्यवस्था
के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक विकास
को दुरुबद कर रहा है।

काला धन : उत्पत्ति के कारक



भारत की भूमिका

घरेलू स्तर पर -

- काला धन अधिनियम, 2015
- बेनामी लोन-देन संचयन अधिनियम 2016
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेनामी लोन-देन पर स्पेशल

इन्वेस्टीगेशन वीथ (JIT) बनाना

- सिंगापुर, मॉरिशस आदि देशों से दोहरा कर परिवार सम्पर्क में संशोधन करना
- भारतीय अणुसंशोधन बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से अग्रिम मुख्य हस्तांतरण (APR) सम्पर्क करना
- विमुक्तिकरण, जस्ट प्रिमानियन
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर -

- ज-20 देशों के साथ मिलकर 'कार्नेशियल' पुष्पान लस्क लोर्स (FATE) का प्रिमानियन जिसमें मनी लोर्स पर राष्ट्रों में आपसी सहयोग किया जाता है
- हाल ही में ब्रिक्स एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने इस पर रोक लगाने एवं समर्थन बढ़ाने की मांग की है

निष्कर्ष:

भारत में टेम्स-जीपी अनुपात केवल 16.1 है जिसका मुख्य कारण कार्गो का

हैं। कर प्रक्रिया का सरलीकरण (GSTN,
प्रोसेस इनसाइर), कर छूटों का व्यवस्थीकरण
कर, राजनीतिक दलों को भाषकर रिटर्न जमा
करने हेतु पाबन्द करके भारत वस दिशा में
समृद्धि कदम उठा सकता है।

7. The national security of the country cannot be strengthened until we focus on intelligence sharing and ensure greater coordination among agencies. Elaborate. Also, highlight the steps being taken by the government to strengthen its intelligence network.

जब तक हम विभिन्न एजेंसियों के मध्य आसूचना साझाकरण (इंटेलिजेंस शेयरिंग) एवं बेहतर समन्वय पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। विस्तारपूर्वक बताइए। साथ ही, सरकार द्वारा अपने आसूचना नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालिए।

किसी भी राष्ट्र की 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के मुख्य कारक विभिन्न 'संस्थाओं' के मध्य सहयोगपूर्ण सम्बन्ध हैं।

भारत में विभिन्न 'संस्थाओं' में सहयोग :

आसूचना साझाकरण हेतु भारत

में विभिन्न संस्थाओं यथा -

(i) कम्प्यूटर इन्फरमेशन रिसोर्स-मैनीन (CCRT-IN)

(ii) NET JARID की स्थापना

(iii) NIC की स्थापना

एवं विभिन्न पुलिस स्टेशनों, रक्षा संस्थाओं में स्थित साबर डीन सापारि कार्यालय हैं।

इन सबके महत्व सहयोग एक आपस
वांछनीय आवश्यकता है क्योंकि

- संसद के अभाव में सुरक्षा बलों का
खतरा जैसे - 1000 में दुर्घटनाएँ
- सार्वजनिक आवागमन में हड़त का खतरा
हाल ही में बीकानेर ज़ोन में
- लोगों की गोपनीयता व जासूसी के
अधिकार की उल्लंघन (SC द्वारा हाल
में मूल अधिकार घोषित किया)
- हाल ही में सार्वजनिक विंग को भारत
की नई पुनर्नीति एवं सुरक्षा नीति
का प्रमुख घटक बनाया गया है
- हार्डब्रिज सारम एवं पुनर्नीति संस्थापन से
बचने हेतु
सरकार द्वारा उठाये गये कदम -
- कम्यूनिटी वॉटरशेड रीसर्च (CGR-
2N)

की गठन'

- अन्ती आसूचना संस्थाओं में एक साथ
ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप का शरणा नाकि आपसी
विश्वास बढ़ोत्तरी हो

- कार्य क्षेत्रों की अपेक्षा आवश्यकता
होने पर त्वरित सूचना संरक्षण एवं सामा
करण पर ध्यान]

इस प्रकार भारत द्वारा सूचना
तकनीक को प्रभावी उपयोग करने का प्रयास
किया गया है जिसे और बढ़ाने, पॉलि
करण की आवश्यकता है)

8. In what ways is the approach of "Act East" Policy different from "Look East" Policy? Suggest certain priority areas on which India should focus upon to fulfill its ambitious geostrategic and economic goals in the region.

"लुक-ईस्ट" नीति की तुलना में "एक्ट ईस्ट" नीति का दृष्टिकोण किस प्रकार भिन्न है? इस क्षेत्र में अपने महत्वाकांक्षी भू-रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे प्राथमिकता क्षेत्रों का सुझाव दीजिए जिन पर भारत को अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

भारत द्वारा पूर्वी एशिया से सम्बन्धों को सुधारने तथा व्यापकता उदात्त करने हेतु 1992 में 'लुक ईस्ट नीति' को अपनाया गया तथा हाल ही में 2015 में इसकी जगह 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' अपनार् गई।

भिन्नता

लुक - ईस्ट नीति

- आर्थिक सम्बन्धों पर अधिक बल
- केवल आसियान राष्ट्रों तक सीमित
- व्यापार की भूमिका सीमित

एक्ट ईस्ट नीति

- आर्थिक सम्बन्धों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्धों पर बल
- पूर्वी एशिया, जापान इत्यादि राष्ट्रों को शामिल करना
- व्यापार एक्ट एशिया के ढांचे के रूप में

भारतीय प्रयास -

⇒ आमरिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना - भारत को पूर्वी एशिया के साथ आमरिक एवं अन्य सम्बन्धों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। हाल ही में भारत द्वारा वियतनाम को परमाणु परीक्षणों से सम्बन्धित किया गया।

- जापान के साथ 'मालाकर सैन्य अभ्यास' करना

⇒ कृषि के क्षेत्र में - पूर्वी एशिया के कई राष्ट्र कृषिगत तकनीकों में अग्रणी हैं जिसमें भारत सहयोग कर सकता है। यथा - म्यांमार से पान आयात

⇒ आर्थिक, व्यापारिक - आसियान भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है जिसे आगे और बढ़ाया जा सकता है।

⇒ क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से - RCEP, आसियान, आसियान रिजनल फोरम, ब्रिक्स, मैकांज गंगा समूह इत्यादि के माध्यम से।

इसके अलावा विभिन्न गतिविधियाँ, पीन को संतुलित करने में प्रयत्न किया जा रहा है।

कारगर हो सकती है 'प्रोजेक्ट भासम' हमें
सहायक हो सकता है

निष्कर्ष: -

भारत विश्व की प्रमुख विकासशील
अर्थव्यवस्था है जो अपनी सामंजस्य के माध्यम
से एक विश्व नीति को कारगर बना सकता है

9. In recent years there has been an increasing convergence between Russia and China on several global issues. What are its implications for India? What steps should be taken by India to protect its national interests?

हाल के वर्षों में रूस और चीन के बीच कई वैश्विक मुद्दों पर समाभिरूपता (कन्वर्जेंस) में निरंतर बढ़ोतरी देखी गयी है। भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए कौन-से कदम उठाए जाने चाहिए?

अमेरिकी नीतियों के बढ़ते उभाव
की कम करने तथा अमेरिका की 'एशिया
पाइपट' की नीति को उत्सिंहित करने में
रूस एवं चीन में आपसी सम्बन्धों की जागरूकता
बढ़ रही है। हाल ही में सीरिया युद्ध, लीबिया
युद्ध, आतंकवाद के युद्ध पर दोनों राष्ट्रों में
समाभिरूपता देखी गई।

भारत के लिए निहितार्थ -

- रूस भारत का प्राकृतिक मित्र रहा है, भविष्य में रूस की चीन की ओर झुकाव भारत के लिए चिन्ता का विषय है।
- भारत और रूस कई क्षेत्रों में सहयोगी हैं परंतु चीन के माध्यम से रूस का पाठ को दृष्टिकार विवर्तित करना भारत के लिए गंभीर।

- 'वन बेस्ट वन रोड प्रेजेंट पर रक्स का चीन' के साथ होना भारत के पक्ष को कमजोर करना है
- 'हाफिल सईद, मंसूर अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में दोनो' राष्ट्रों का इंतजार करना
- 'अफगानिस्तान में तालिबान से सम्बंध स्थापना का उद्घास भारत के लिए घिनौनीय भारत द्वारा उठाये जाने वाले कदम'.

- भारत को 'अमेरिका के साथ-साथ रक्स से भी अपने पुराने सम्बंधों का नवीनीकरण करते हुए जुड़ कर करना चाहिए'
- 'अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में राष्ट्रीय सुरक्षा-उद्यम की नीति के अनुसार सम्बंधों में विविधीकरण का उद्घास करना चाहिए जैसा कि भारत - जापान, भारत - जर्मनी, EU, इत्यादि
- 'हथियार आयात हेतु अन्य राष्ट्रों पर'

निर्भर रहने की अपेक्षा स्वदेशी परबल, वेक
इन इंडिया को जोत्साहम

सारांशतः भू-राजनीतिक एवं
आर्थिक आवश्यकताये' यथदिव्यादी राजनीति का
निर्धारण करती हैं', अतः भारत को स्वयं
के साथ अन्य राष्ट्रो' से सम्बन्ध विस्तार
करना चाहित है - एशिया पॉलिटी,
मध्य एशिया की नीति इत्यादि।

10. After remaining peripheral to India's foreign policy priorities, the Indian Ocean has received some attention in recent years. Nonetheless, given the significance it holds, involvement of actors with diverse interests and existing challenges, it is imperative that India redoubles its efforts in shaping the future of the region. Discuss.

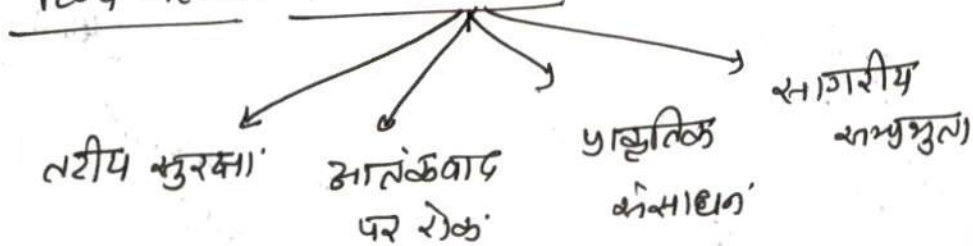
दीर्घकाल तक भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में हाशिये पर रहने के उपरान्त, हिंद महासागर ने हाल के वर्षों में कुछ ध्यान आकर्षित किया है। इसके अंतर्निहित महत्व, विभिन्न हितों वाले देशों के शामिल होने और मौजूदा चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह आवश्यक है कि भारत इस क्षेत्र के भविष्य को आकार प्रदान करने में अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाए। चर्चा कीजिए।

हिंद महासागर भारत का प्रमुख भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध रहा है परंतु विगत कुछ वर्षों पहले भारत द्वारा इसकी प्राथमिकता पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था - बिस्मटेक की स्थापना 1947 में हुई परंतु इसको उभारी प्रियाखित नहीं किया गया।
हाल के घटनाक्रम -

भारत द्वारा हिंद महासागर की अपनी विदेश नीति में एक प्रमुख तत्व आकार आशिल किया गया है तथा 'एशिया-पैसिफिक इकोनॉमी' के माध्यम से सागरीय योजनी राश्ट्रों से सम्बन्ध स्थापना का प्रयास किया जा रहा है।

है -

- लिपिक राष्ट्रों के साथ 'जयपुर छोड़नाफा'।
- बिस्मटेक, मेकांग गंगा समूह इत्यादि की प्रवर्धन करना
- बांग्लादेश, भारत, म्यांमार (BBM) मॉटर वाहन सम्मिलित करना
- समुद्री वायरे की पर रोक लगाने हेतु उपास
- विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल व्हील रिबू (2016) का आयोजन
- चाबहार बंदरगाह का विकास
- अफ्रीका राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापना का उपास

हिन्द महासागर का महत्व -हिन्द - महासागर चुनौतियाँ -

- हिन्द महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों में अलग-2 राजनीतिक, आर्थिक प्रणाली
- परस्पर विश्वास, सहयोग की कमी
- भूट, विवाद, आतंकवाद यथा - महत्व प्रशिक्षण

भारत- पाक, सम्रायल मिलिती

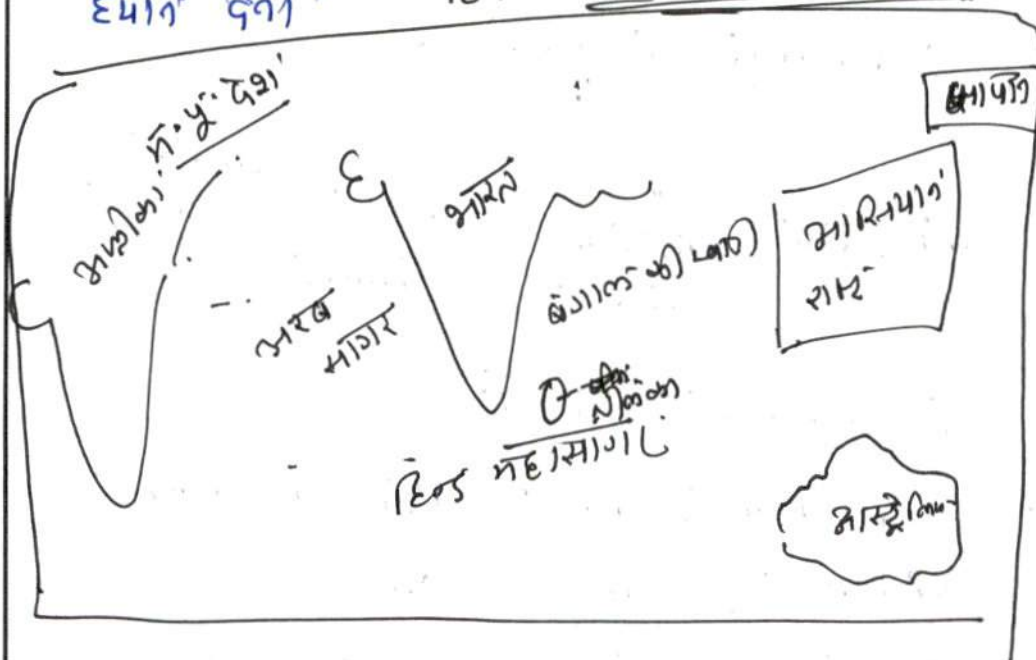
- विकास की दृष्टि में जी०, सामाजिक आर्थिक विद्यमान

भारत द्वारा पद्यासों की आवश्यकता -

भारत हिन्द महासागर की कगली

આજી ૬, ૩૧.

- 'ब्लू इकोनॉमी' को आकार उदाग करने, महत्व उदाग करना
- आपसी सहयोग का उपास, सागरीय प्रकृति रक्षक जैसी कार्यवाहियां करना
- सफ़ाई पायरेजनी, लचील सुस्काई कापादि मुदोपन दियं महसागर : श्रु-राजनीतिक महत्त्व



11. What are the objectives and key achievements of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)? Also, highlighting India's association with the Commission, identify its influence on various domestic legal regimes.

अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ: UNCITRAL) के उद्देश्य और प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? साथ ही, इस आयोग के साथ भारत की संबद्धता पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न घरेलू विधिक व्यवस्थाओं पर इसके प्रभाव की पहचान कीजिए।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख समेती है जो व्यापार एवं निवेश सरलीकरण के मुद्दे पर उत्पादों सिद्धान्त (विस्तरे जाने के सिद्धान्त) पर कार्य करती है

उद्देश्य -

- राष्ट्रों के मध्य सहयोग की स्थापना
- व्यापार मुद्दों पर विवाद सुलझाना
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जटिलता का प्रभाव
- अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाथवे, समुदाय के नीचे मुद्दों से निपटना

प्रमुख उपलब्धियां

विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अंशिक वादी नीतियां	विभासनीय विभिन्न राष्ट्रों में हरी	अंतरराष्ट्रीय समन्वयक अभिनय
--	--	-----------------------------------

रूपलाब्धियाँ -

- खास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सरलीकरण
- विपक्ष विधरिण के माध्यम से विकास -
विकाशशील राष्ट्रों में इसी का करना
- WTO के सदस्य राष्ट्रों में व्यापार, निवेश
के मुद्दों पर सहयोग करना
- आर्थिक, साधनों का समतुल्य वितरण

UNCTRAL एवं भारत -

UNCTRAL का भारत संस्थापक
सदस्य रहा है तथा विभिन्न गतिविधियों में
भारत की सकरात्मक भागीदारी रही है।

- UNCTRAL के विनियम समझौते में
भारत का योगदान रहा है।
- भारत UNCTRAL की ^{मुख्य} दक्षिण-सहयोग की
नीतियों का समर्थक रहा है।

इस प्रकार भारत एक प्रमुख
अंतराष्ट्रीय अर्थ वित्त संगठनों का सदस्य
के तहत सम्बन्ध भारतीय की अन्तर्राष्ट्रीय

विनिय संस्थाओं में बरती आगीदारी का
परिचायक हैं

12. What are the issues and challenges faced by Indian migrants in the Gulf countries? Enumerate the steps taken by the Indian government to address these.

खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे एवं चुनौतियाँ क्या हैं? इनसे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध कीजिए।

खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीय नागरिकों के माध्यम से भारत की आर्थिक सुरक्षा (रेमिटेंस), सांस्कृतिक सम्बन्ध, अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ्ट पावर के रूप में स्थापना में सहभाग्य मिली है।

प्रवासी भारतीय पुरुष चुनौतियाँ व मुद्दे

- सुरक्षा - प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर पुरुष मुद्दा रहा है क्योंकि ये राष्ट्र आंतरिक अतिरिक्तियों से घिरे हुए हैं।
- वैतन - भारतीय प्रवासियों को बहुत कम वेतन पर काम करने हेतु मजबूर किया जाता है।
- कमाली व्यवस्था - कमाली सिस्टम के माध्यम से भारतीय मजदूरों का शोषण।
- मानवाधिकार हानि के माध्यम से शोषण इसके अलावा भारतीय महिलाओं व बच्चों की लस्करी, सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं।

भारत सरकार द्वारा उठाये कदम -

- भारत द्वारा मध्य-पूर्व के राष्ट्रों से इस हेतु द्विपक्षीय समझौते किये गये हैं जिसके माध्यम से भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा का प्रयास करता है।
- हाल ही में यमन में जोबेन शहरे के माध्यम से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित कराया गया।
- भारत सरकार द्वारा रिवर डिलीवरी के माध्यम से प्रवासी भारतीयों की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस प्रकार भारतीय सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा हेतु प्रयास किये गये हैं परंतु इस हेतु -

- विभिन्न विदेश कार्यालयों से समन्वय का प्रयास करता।
- अर्थशास्त्रिक पार्सपोर्ट आदि पर रोक लगाता।

- भारतीयों के विकास होने वाले मापकों का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उभान आवश्यक है।

13. The recent breakthrough in the Civil Nuclear field is a sign of India-Japan relations moving beyond the calculations of complementarities and cooperation. Analyse in view of the multiple factors shaping India-Japan relations.

नागरिक परमाणु क्षेत्र में हाल ही में प्राप्त सफलता भारत-जापान संबंधों का अन्योन्याश्रितताओं (अनुपूरक) और सहयोग से परे जाने का चिह्न है। भारत-जापान संबंधों को आकार प्रदान करने वाले विविध कारकों का विश्लेषण कीजिए।

भारत - जापान सम्बन्ध आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्धों की दृष्टि का परिचायक है।

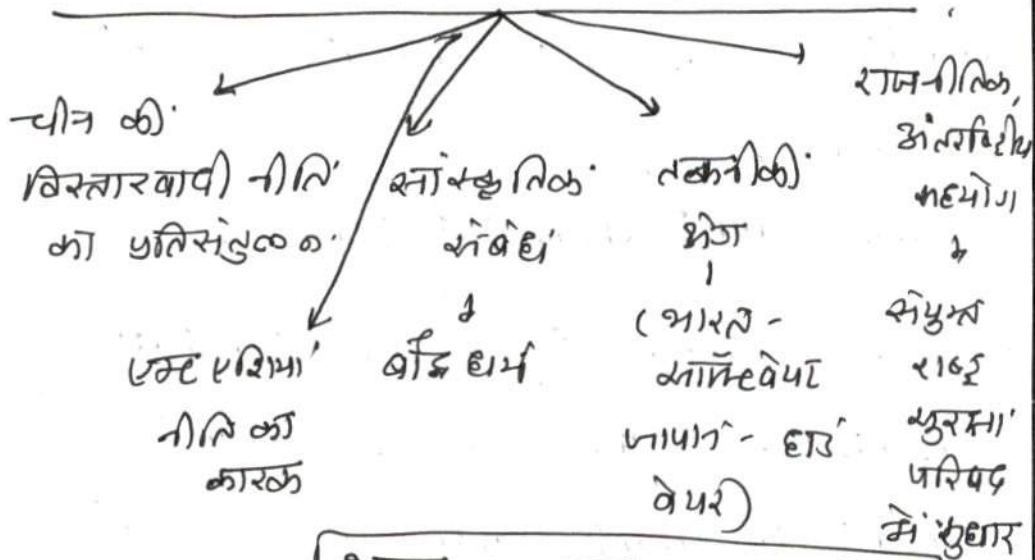
भारत जापान सहयोग के मुद्दे -

- नौकरी की हस्तान्तरण - दिल्ली भेड़ो, अहमदाबाद, मुम्बई ब्लॉक डेन राजादि के माध्यम से जापान भारत को नौकरी काहायत कर रहा है।
- आर्थिक सम्बन्ध - भारत - जापान के मध्य मजबूत आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध है।
- अंतरिक्ष, सागर सुरक्षा, आपदा - प्रबंधन इत्यादि मुद्दों पर भारत - जापान में आपसी सहयोग है।

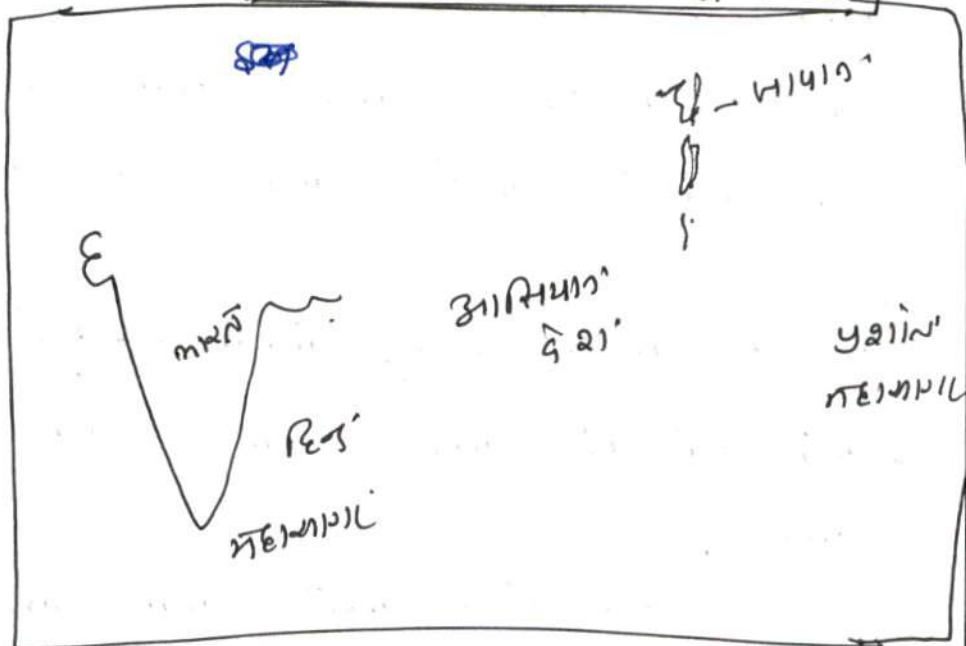
दाल ही में भारत - जापान द्वारा चीन के खिलाफ एकजुट होगा यथा डोकलास

मुझे पद, ऊतरी कोरिया पर भारत द्वारा जापान
को साथ देना इनके सम्बन्धों को सहयोग
से परे प्राकृतिक प्रिण्टों की श्रेणी में लाता है

भारत - जापान सम्बन्ध : विविध कारक



भारत : जापान → भू-स्थिति



भारत - व्यापार सम्बन्धों 'यद्यपि सहयोगपूर्ण
हैं' तथापि आपसी झूठे पथा - 'WTO में'
व्यापारिक विवाद को सुलझाकर सम्बन्धों को
और सुदृढ़ किया जा सकता है।

14. The Commonwealth grouping has been accused of talking about ideals that it does not uphold and wasting the resources of governments. Critically analyse the statement and comment on the relevance of the Commonwealth grouping in present times.

राष्ट्रमंडल समूह पर उन आदर्शों के संबंध में चर्चा करने जिनका स्वयं इसके द्वारा अनुसमर्थन नहीं किया जाता एवं सरकारों के संसाधनों का अपव्यय करने के आरोप लगते रहे हैं। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए एवं वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल समूह की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए।

राष्ट्रमंडल समूह उन राष्ट्रों का समूह है जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश के बिछार रहे थे। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, द. अफ्रीका, इंडोनेशिया आदि राष्ट्र शामिल हैं।
राष्ट्रमंडल राष्ट्र : - पुनर्निर्माण -

- संयुक्त राष्ट्र के नीतियों, कार्यक्रमों का दोहराव
- सदस्य राष्ट्रों का घटा विवेक
- विभिन्न आगीदारी में कभी (केवल भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका) जैसे राष्ट्रों द्वारा नीतियों की शसंश्लेषण नहीं
- राष्ट्रमंडल व नीतियों को धारण कर बदलने का भी आरोप लगाते हैं

राष्ट्रमंडल सश्रूट : प्रासंगिकता :-

- राष्ट्रमंडल सश्रूट द्वारा आतंकवाद पर लगाने लगे हैं चर्चा
- राष्ट्रमंडल ऐसा संगठन जिसने अपनी नीतियों के विकास करते हुए अपने सदस्यों
- पाकिस्तान को दृष्टिगत किया
- राष्ट्रमंडल राष्ट्र विकासशील एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य बढ़ते सहयोग के परिचायक हैं
- सागरीय तस्करी, सीमा पर आतंकवाद, अणुवाद पर आपसी सहयोग

राष्ट्रमंडल : भारत के लिए निहितार्थ

- भारतीय नेतृत्वशीलता का परिचायक
- ऊर्जा सुरक्षा (यथा - ऑस्ट्रेलिया से परमाणु करार स्थापित)
- प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्रों में
- अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में सॉफ्ट पावर स्तंभित राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थापित

- संस्थानों का 'गैर' मजदूर होने में सहायता
- NSP (न्यू मिथिल 'सप्लायर्स ग्रुप') की
संस्थानों में सहायता।

इस प्रकार 'वाइडमैड' को वर्तमान
परिप्रेक्ष्य के अनुसार नीति निर्धारण का प्रयास
कर सामाजिक उपयोगिता बनाया जा
सकता है।

15. ISRO has successfully flight tested the Reusable Launch Vehicle-Technology Demonstrator (RLV-TD). Discuss the significance of RLV and bring out the differences between RLVs and conventional Launch Vehicles (LVs). What are the challenges in successful execution of RLVs?

इसरो (ISRO) ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन-तकनीक प्रदर्शक (रियूजेबल लॉन्च व्हीकल-टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर: RLV-TD) की उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। RLV के महत्व पर चर्चा कीजिए तथा RLVs एवं पारंपरिक प्रक्षेपण वाहनों (लॉन्च व्हीकल: LVs) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। RLVs के सफल कार्य-निष्पादन में क्या चुनौतियां हैं?

इसरो द्वारा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन 'टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर (RLV-TD)' के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख सम्पन्नता प्राप्त की गई। यह वाहन एक डोमिन को पुनरा उपयोग का लाभ दाने तथा विश्वसनीयता बढ़ाने की प्रमुख कारक है।

RLV - महत्व

- भारत की व्यावसायिक क्षमता में सुधार
- कम लागत में अधिक प्रक्षेपण
- भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार
- इसरो को व्यावसायिक उपयोग में कम लागत यथा - रेवेन्यू जनरेशन
-

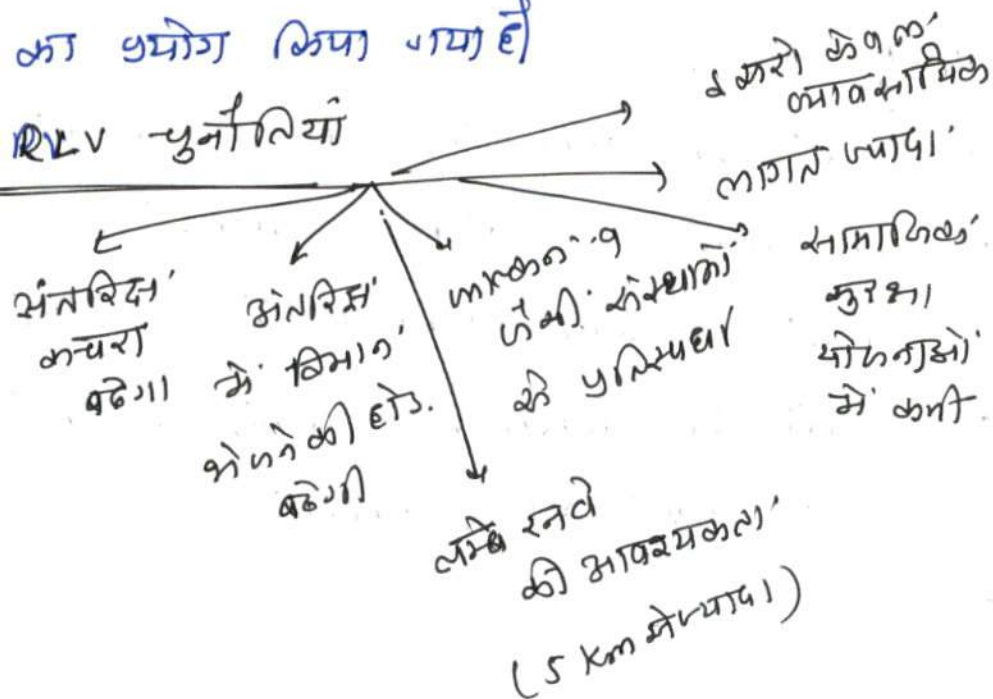
RLV-TD एवं LV में अंतर -

RLV-TD में इंजन की दुबारा उपयोग किया जा सकता है, पुराने लॉच व्हीकल में नहीं।

RLV-TD में पंचवी का उपयोग इस प्रकार किया जायेगा कि आसानी से लैंडिंग हो सके जबकि पुराने तकनीक में आकाश में ही लैंडिंगल समाप्त हो जाना था

इन दोनों में मुख्य अंतर व तकनीक का है जिसमें RLV-TD में डिस्कोन्टेन का उपयोग किया गया है

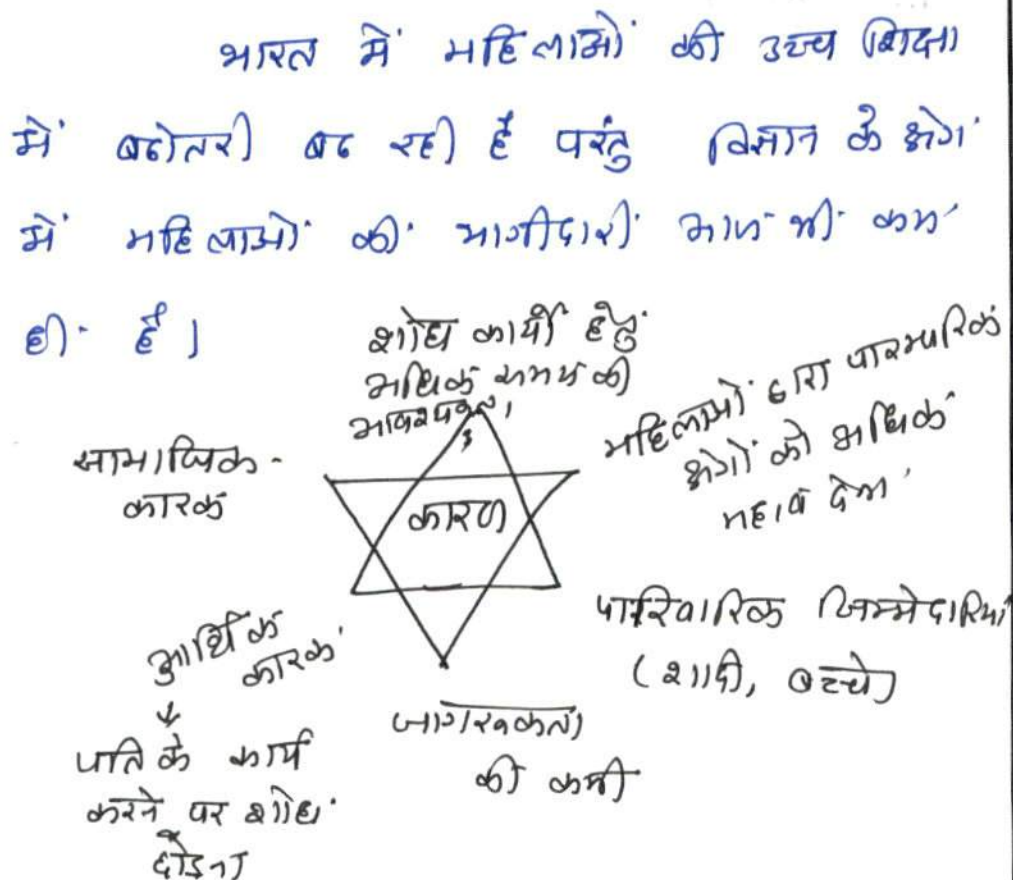
RLV चुनौतियाँ



उल्लेखनीय है कि हमारे की विवेकशीलता
में बदोल्दी हुई है इसीलिए भारत के
आंतरिक आर्थिकता की बढ़ावा देने हेतु ऐसे
उद्योग आवश्यक हैं।

16. Women constitute just 14% of science researchers in India, though they are no longer a minority within higher education when it comes to STEM. Analyse the reasons for this state of affairs and discuss how it can be addressed.

यद्यपि भारत में विज्ञान शोधकर्ताओं की कुल संख्या में महिलाएं केवल 14% ही हैं, किन्तु STEM के संदर्भ में उच्च शिक्षा के अंतर्गत वे अब अल्पसंख्यक नहीं हैं। इस स्थिति के कारणों का विश्लेषण कीजिए और चर्चा कीजिए कि इसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है?



समाधान -

- सरकार को महिलाओं की भागीदारी इस क्षेत्र में बढ़ाने हेतु जागरूकता अभियान चलाया चाहिए
- प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों, प्रख्यात

शोध कलरुओ' के नरहयन से नरहिलरओ' को
शोध की उपयोजितर बनरनर ।

- धर पर हीं रहकर शोध हेतु शेरसरर
देनर
- शोध में व्यवधरन आने पर दुबरर शुरु करे
में सहरयत देनर
- सोशल मीडिर, NLU शरररि की सहरयत
से सोशल कंनेक्शंस की उपरस करनर
सरकरर करर किये गये उपरस -
- सरकरर करर गुवर्नर नररि (NIDM),
गुवर्नर इन्सपिरर (INSPIRE), नरहिलर
वैज्ञरनिकों को दरगुति देनर शरररि कररुशन
चलरपे गये हैं।

वस्तुतः सभर उपरस रररररररररर
परंतु पयत्ति नहीं है, इस हेतु अपरक
दुबरर कररुशन चलरने नरने की ररररररररर
है।



17. What do you understand by Internet Governance? Has the recent development of ICANN becoming free from the US government solved the issues of Internet Governance? What should be the way forward?

इंटरनेट गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से ICANN के मुक्त होने की हाल ही की घटना ने इंटरनेट गवर्नेंस के मुद्दों का समाधान किया है। आगे की राह क्या होनी चाहिए?

इंटरनेट गवर्नेंस से तात्पर्य 'इंटरनेट' तथा सूचना तंत्रों/डिजिटल के माध्यम से गवर्नेंस को बढ़ावा देना है।

ICANN -

यह एक अन्तर्राष्ट्रीय इंटरनेट एजेंसी है जो पहले USA के वाणिज्यिक विभाग का कार्य देखती थी। हाल ही

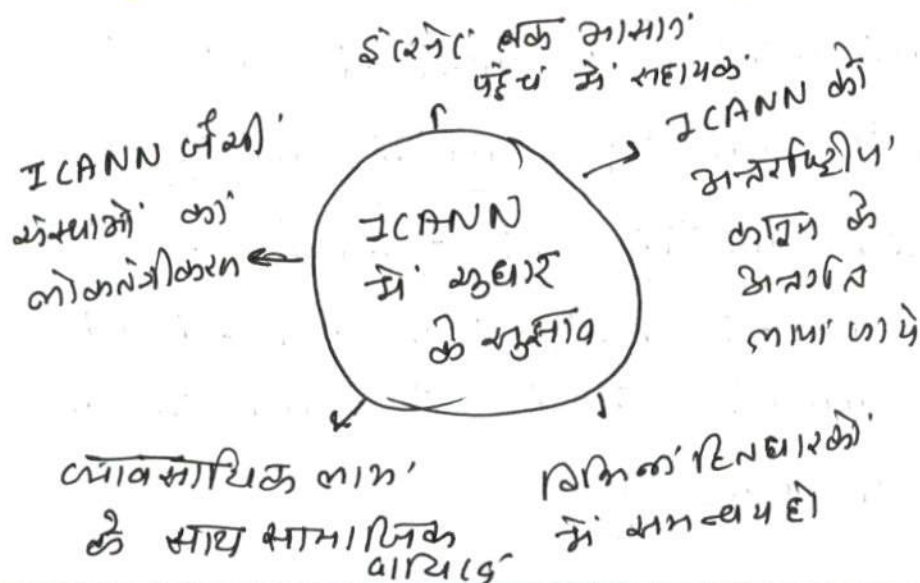
में इसका सम्प्रभुता समाप्त हो गई पर इसने स्वतंत्र एजेंसी के रूप में "भासे-दारी वायिप" के आधार पर कार्य का निष्पत्ति लिया है। (मराकेश, मोरक्को में)

इंटरनेट गवर्नेंस - मुद्दे, चुनौतियाँ :-

- यह एक स्वतंत्र एजेंसी होनी इसलिपे व्यापारिक मामलों में लाभ को हथगत दे सकती है।

- अग्री भी USA का नियंत्रण
 - विभिन्न क्षेत्रधारकों, हितधारकों में सहयोग की रूपरेखा स्पष्ट नहीं।
 - अग्री एक जोड़ कावून के अन्तर्गत नहीं है
- इंटरनेट गवर्नेंस; लाभ

- इंटरनेट पर अग्री राष्ट्रों में भागीदारी बढ़ेगी
- संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का पसपानी रवैया समाप्त होगा
- इंटरनेट के मौलिक अधिकार जिसे हाल में W.N द्वारा स्वीकार किया गया, की पहुंच बढ़ाने में सहायक होगा

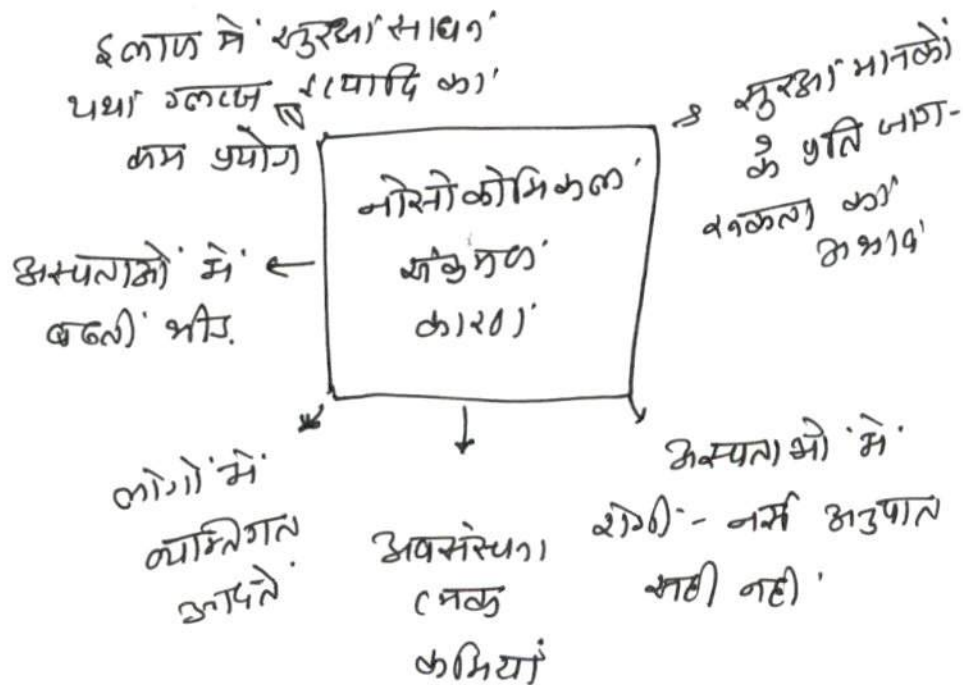


अंतर: 2022 को वैश्विक लक्ष्यों के
अनुसार प्रभावी बनाने लाय - समावेशी,
विकास की पहलों की जा सकती हैं

18. Increase in the cases of nosocomial infections has emerged as a major concern in India. What are nosocomial infections? What are its causes and why is it a major concern in India? Identify the measures required to combat these infections.

भारत में नोसोकोमियल संक्रमण (nosocomial infections) के मामलों में बढ़ोत्तरी एक प्रमुख चिन्ता के विषय के रूप में उभरी है। नोसोकोमियल संक्रमण क्या है? इसके कारण क्या हैं और यह भारत में एक प्रमुख चिन्ता का विषय क्यों है? इन संक्रमणों की रोकथाम करने हेतु उपायों की पहचान कीजिए।

नोसोकोमिकल संक्रमण से नात्पर्य भूम्य-
नाओं में इलाज के दौरान मिलने वाले
संक्रमण से हैं।



भारत : चिन्ताओं

- भारत एक विशाल जनसंख्या एवं गरम जलवायु वाला राष्ट्र है, अतः मौसमी बीमारियों का संक्रमण फैलना रहता है।
- भारत में अस्पतालों में भौतिक एवं सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की कमी है जिससे प्रकृति या मानकों का पालन नहीं किया जा सकता।
- इससे रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र पर दबाव में बढ़ोतरी होती रहती है।

बचाव के उपाय -

- लोगों में सामाजिक तरीकों, मोशल मीरमा इत्यादि के माध्यम से संक्रमण के खतरा जागरूकता बढ़ाई जाये।
- हाथ धोने की आदत का विकास।
- डॉक्टरों, नर्सों द्वारा सुरक्षा मानकों का

पालन कोर करना ।

- PHC जैसे छोटे स्तरों पर दीवार-लेख
पंचायत के माध्यम से शैक्षणिक जागरूकता
का विकास ।

इस प्रकार नैसर्गिकोमिकल संक्रमण
को गहवारी करने से पहले सीमित करने की
आवश्यकता है)

19. There is a growing concern that robots, automation and AI will transform the labour markets and lead to massive job loss across the world. Comment. Also mention the steps that can be taken to mitigate the impact of increased automation and AI.

इस विषय में चिंता बढ़ती जा रही है कि रोबोट, ऑटोमेशन (स्वचालन) एवं AI, श्रम बाजार को रूपांतरित कर देंगे और परिणामस्वरूप विश्व भर में बड़े पैमाने पर रोजगारों की हानि होगी। टिप्पणी कीजिए। बढ़ते ऑटोमेशन (स्वचालन) एवं AI के प्रभाव को कम करने हेतु उठाए जा सकने वाले कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलि-
जेंस, ऑटोमेशन जैसे माध्यम मनुष्य
श्रम को आसानी से, तबलें उड़िया-
अपनाते तथा लाभ को अधिकतम करने
हेतु उपयोग में लाये जाते हैं।

चिंता -

- ऑटोमेशन एवं AI दोनों श्रम बाजार को प्रतिस्थापित करने की संभावना है।
- वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत में 69% नौकरियों पर ऑटोमेशन व AI के कब्जा रहता है।
- विविध क्षेत्रों में विभिन्न संरचनाओं, ठीकों द्वारा इसका उपयोग शुरू भी हो रहा है।

आया है।

- मानवीय क्षमता से बहुत ज्यादा कार्य करने में सक्षम होने के कारण यह वैश्विक बाजार को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

ध्यान - चालक रहित कारें, रोबोट इत्यादि का प्रयोग

लाभ -

- कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी
- लाभ में बढ़ोतरी
- कम विवादों के साथ ज्यादा उत्पादन
- दुर्घटियों इत्यादि का कम खर्च
- यदि नौकरियां कम होंगी तो आत्मोपेक्षा इत्यादि की संचालनीयता के लिए नई नौकरियां पैदा की जाएंगी।

उठाये जाने योग्य कदम -

- आत्मोपेक्षा एवं AI का उपयोग कम खर्चों में ही जहां कुशलता में की आवश्यकता ज्यादा

- निम्नलिखित कार्यों, खानों, अंतरिक्ष क्षेत्र में
ज्यादा उपयोग लोग चाहेंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि AI
आपकी वास्तविकता है लेकिन इसके
लाभ व दुर्गुणों में सामंजस्य बिठाते
हुए अधिकतम उपयोग का प्रयास करना
चाहिए।

20. The importance of IPRs as a marketable financial asset and economic tool needs to be recognised. Elaborate. In this context, analyse how the National Intellectual Property Rights (IPR) Policy intends to lay the future roadmap for intellectual property in India.

विक्री-योग्य (विपणनयोग्य) वित्तीय परिसंपत्ति एवं आर्थिक उपकरण के तौर पर IPRs के महत्व को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। विस्तारपूर्वक बताईए। इस संदर्भ में, विश्लेषण कीजिए कि राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) नीति भारत में बौद्धिक सम्पदा का भावी रोडमैप किस प्रकार निर्धारित करना चाहती है?

बौद्धिक सम्पदा अधिकार किसी राष्ट्र में नवीन विचारों, उपकरणों, आविष्कारों के प्रयोग को बढ़ावा देता है।

IPR - आर्थिक महत्व -

- IPR के माध्यम से पेटेंट द्वारा कोई राष्ट्र अपने स्व मागरिष्ठों की शोध, अनुसंधान प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है।
- IPR के माध्यम से नवीन तकनीक आती है जिससे लगातार कम होती-है, मूल्यरूप उत्पादन में घटोली, JDD में हटि।

IPR - चुनौतियाँ

- पेटेंट, दवादि के कारण 'जेनरिक' दवा'

निम्नलिखितों को हानि क्योंकि वे अधिक
अभय तक अपनी सोच नहीं बना पायेगे।
या

भारत : राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति

- 2016 में भारत द्वारा अपनी नई 2019 नीति को घोषित किया गया है जिससे किन्नर भारत अपने आर्थिक संसाधनों, अनुसंधान एवं शोध को बढ़ाने हेतु बौद्धिक अधिकारों को बढ़ावा देगा।
- यह नीति सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक योग्यता के तहत सम्बन्ध का प्रयास करती है।
- अनिवार्य लावसेंसिंग का प्रावधान।

इस प्रकार नव 2019 नीति

भारत को अपने समाजवादी स्वरूप वाले
आवाजवादी मॉडल के अनुसंधान रीउन्फ
बढ़ाने का प्रयास करती है।

